राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

सम्पादकीय

सच सामने आया!

यदि 99 फीसदी पुराने नोट बैंकों तक पहुंच गए तो इसका मतलब सीधा और साफ है। या तो कालाधन था ही नहीं और यदि था फिर वो तो सफेद हो गया।

आखिर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने नोटबंदी की असलियत जनता के सामने ला ही दी। आठ नवंबर, 2016 को एक हजार व पांच सौ के नोट एक झटके में बंद करने के सरकारी फैसले से लगा था कि कालेधन पर अब चोट होगी। देश के करोड़ों लोगों ने महीनों परेशानियां भी झेलीं। कहीं शादियों का जश्न फीका पड़ गया तो कहीं हार्ट अटैक से मौत की खबरें आईं। छोटे कारोबारियों का रोजगार चौपट होने व हजारों युवाओं की नौकरियां जाने का कड़वा सच भी सामने आया। बावजूद देश की जनता को विश्वास था कि इतना बड़ा फैसला सोच-समझकर ही लिया होगा। लगभग दस महीने बाद आई रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने जनता को सकते में जरूर डाला है। जनता को लग रहा है कि देश में कालेधन नाम की चीज है ही नहीं। यदि 99 फीसदी नोट बैंकों तक पहुंच गए तो मतलब सीधा और साफ है। या तो कालाधन था नहीं और अगर था तो सफेद हो गया। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी। कहा सरकार का नोटबंदी का फैसला सही था और उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। नोटबंदी के तीन बड़े मकसद थे। पहला कालाधन बाहर लाना, दूसरा आतंकवाद पर नकेल और तीसरा नकली नोटों को चलन से बाहर करना। कालाधन तो बाहर आया नहीं। रही बात आतंकवाद पर नकेल कसने की। नोटबंदी के शुरुआती दिनों में तो आतंककारी वारदातें भी थमी सी लगती थीं और पत्थरबाजी भी। लेकिन धीरे-धीरे इसमें भी तेजी आ गई। घुसपैठ, पत्थरबाजी फिर हो रही है। नोटबंदी का तीसरा मकसद भी सफल होता दिख नहीं रहा। दो हजार व पांच सौ रुपए के नए नोट आने के साथ ही नकली नोट भी पकड़े जाने लगे थे। विपक्ष को छोड़ देश की अधिकांश जनता नोटबंदी के पक्ष में थी। यह सोच कि सरकारी नीयत ठीक है तो नतीजे भी सकारात्मक आएंगे। पर अभी तक तो वैसा नजर नहीं आ रहा। आम आदमी भी कालाधन बाहर आते देखना चाहता है। आतंकवाद को कुचलते हुए नकली नोटों को नष्ट होते हुए भी देखना चाहता है। पर ये होगा कैसे? सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़े भी चिंताजनक हैं। गत वर्ष की पहली तिमाही की 7.9 फीसदी जीडीपी घटकर 5.7 फीसदी रह गई है। इसे समझने की जरूरत है। एनडीए सरकार का दो तिहाई समय तो पूरा हो चुका है। शेष बीस महीनों में सरकार क्या करके दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी।

आज का कार्टून

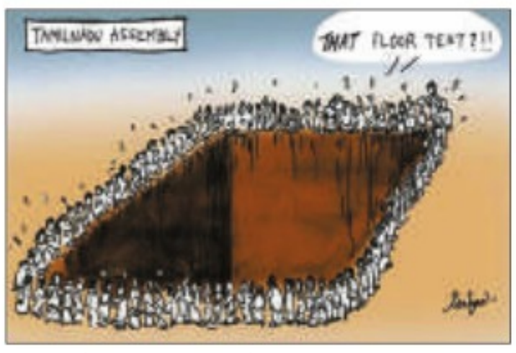

तमिलनाडु के राजनीतिक हालात को दर्शाता व्यंग्य। - साभार : द हिन्दू

बोधि वृक्ष : जीवन दर्शन

व्यक्ति का चेहरा नहीं, चरित्र महत्वपूर्ण होता है

मुनि तरुणसागर

कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात जैन संत

संसार में व्यक्ति का चेहरा नहीं, चरित्र पूजा जाता है। व्यक्ति का गोरा रंग दो-चार दिन ही अच्छा लगता है। पर अच्छा व्यवहार जीवन भर अच्छा लगता है। कुदरत द्वारा चेहरे को जो रंग इंसान को मिलना था, वो जन्म के समय मिल गया। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हां, हम भले ही चेहरे का रंग नहीं बदल सकते, पर अपने जीने का ढंग तो बदल ही सकते हैं। हमारे जीवन के विकास में चेहरे की भूमिका 15 फीसदी है जबकि हमारे चरित्र की भूमिका 85 फीसदी होती है। इसलिए इंसान के लिए चेहरा नहीं चरित्र महत्वपूर्ण होता है।

विश्व विचार : नेपाल

मुद्रा में सुधार: बिगड़ भी सकता है भुगतान संतुलन

बीते कुछ महीनों में डॉलर के मुकाबले नेपाली मुद्रा में पांच फीसदी का सुधार हुआ है। बीते वर्ष 29 अगस्त को नेपाली रुपया 107.60 रुपए प्रति डॉलर था जो अब 102.55 रुपए आ गया। यद्यपि देखने और सुनने में यह स्थिति अच्छी लगती है लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे आयातित वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होंगी। इन हालात में देश की खपत में भी वृद्धि होगी। लेकिन, डॉलर के इस मूल्यह्रास से व्यापार घाटा और अधिक बढ़ सकता है क्योंकि इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव देश के निर्यात पर पड़ने वाला है। राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्मा के मुताबिक चूंकि डॉलर के मुकाबले नेपाली मुद्रा कम मिलेगी इसलिए विदेश में काम करने वाले नेपाली नागरिकों द्वारा देश भेजे जाने वाले धन पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। नेपाली नागरिकों द्वारा देश भेजे जाने वाले धन में कमी आएगी और आयात भी बढ़ा हुआ होगा तो भुगतान संतुलन का संकट भी बन सकता है।

(नेपाल के अखबार द हिमालयन टाइम्स के ओपीनियन पेज से साभार)

भारत में खेती एक बड़ी आबादी के लिए जीवन का आधार है। बाजारवाद की नजर पड़ने से फसली बीज आम किसान के लिए महंगा सौदा हो रहे हैं। प्रकृति की इस देन में किसानों के बीच आखिर बाजार बिचौलिया क्यों बने। बीज पर किसान का पहला हक है, कंपनियों का नहीं। इसे आंदोलन के रूप में सामने लाना होगा...

बीज पर कंपनी नहीं, किसान का हक

वंदना शिवा
पर्यावरणविद्, कृषि मामलों की विशेषज्ञ

राइट टू लाइवलीहुड और सिडनी पीस प्राइज से सम्मानित, पुस्तक 'द सीड ऑफ डेथ' की लेखक

हर बीज में भविष्य छिपा है। अतीत के विकास को संजोए बीज के भीतर भविष्य की अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। बीज मात्र जीवन का स्रोत नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की नींव है। लाखों-करोड़ों वर्षों से बीज इस प्रकार स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है कि इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर विविधता पूर्ण समृद्धि दिखाई देती है। हजारों वर्षों से किसान, खास तौर पर महिलाएं स्वतंत्र रूप से बीज को परस्पर साझेदारी और प्रकृति के साथ मिल कर बीज की विविधता को कुछ इस प्रकार विकसित कर रही हैं कि प्रकृति प्रदत्त उपहार को विभिन्न संस्कृतियों की आवश्यकता अनुरूप अपनाया जा सके। दरअसल, जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता ने ही परस्पर एक दूसरे को विकसित किया है या यूं कहें, आकार दिया है। बीज खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी है और जीवन के भावी विकास का स्रोत भी। इसलिए इन बीजों का संरक्षण कर इन्हें भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित करना हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी। बीज उगाना और किसानों के बीच इनका परस्पर आदान-प्रदान जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने का आधार है। आज प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को हिंसा और अन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। बीज की स्वतंत्रता पर होने वाले खतरे का असर मानव जीवन और हमारे ग्रह दोनों पर ही पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से बीजों का विकास रोकने के भी प्रयास हो रहे हैं। जीवाणु रहित और एक ही बार (सिंगल यूज) के लिए उपयोगी बीज तैयार कर और उनका पेटेंट करवा कर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर के साथ ही भारत में भी इस प्रकार की परिपाटी चलन में है। हमारे यहां किसी भी उत्पाद के पेटेंट से आशय है- उस उत्पाद का स्वामित्व, निर्माण, बिक्री का अधिकार उसी व्यक्ति या संस्था को होगा, जिसने पेटेंट करवाया है। इस प्रकार एक बीज के पेटेंट का मतलब तो यह हुआ कि एक जीव को इस प्रकार परिभाषित किया जाना जैसे वह किसी कॉरपोरेशन का कृत्रिम उत्पाद हो। मेरी राय में यह पूर्णतः अवैज्ञानिक तरीका है, क्योंकि बीज स्वतः स्फुटित, स्वविकसित और स्वतः नवीनीकृत होने वाले एवं स्ववृद्धि करने वाले जैव तंत्र हैं। बीज कोई मशीन नहीं है। इसलिए बीज का पेटेंट करना मेरे हिसाब कतई न्यायविरुद्ध और अनैतिक है। बीज के पेटेंट का मतलब है यदि कोई किसान बीज का संरक्षण कर रहा है तो वह एक प्रकार से 'एक बुद्धिमान संपत्ति चोर है।' लेकिन इसका अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। यह ऐसी प्रणाली है, जिसके तहत बीज पर व्यावसायिक एकाधिकार हो गया है। इसके तहत कुछ कंपनियों द्वारा बीज की आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। ये सब कुछ बाजारवाद का दुष्परिणाम है जो कि किसानों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ के रूप में सामाने आता है। इस समूची प्रक्रिया से आखिरकार ये नतीजा यह होता है कि किसान मजदूर बन कर रह गए हैं। जहां बीज के मामले में स्वतंत्रता समाप्त हुई, आप समझो कि किसान भी स्वतंत्र नहीं रहा। किसान बीज के मामले में अपनी आजादी को खो देता है। बाजारवाद के कारण पैदा हुई स्थिति में किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक पहल की गई है। हमने 'नवदान्य' की शुरूआत की है। नवदान्य का अर्थ है नौ बीज, जो जैव विविधता की समृद्धि का प्रतीक हैं। इसका आशय नया उपहार भी है यानी बीज का तोहफा, जो कि जीवन का स्रोत है। खेत में फसल लहलहाने के लिए जरूरी है बीज को लेकर आजादी। वर्ष 1987 से हम बीज अखण्डता और बीज स्वतंत्रता (बीज स्वराज) के लिए संघर्षरत हैं। नवदन्य जैसे आंदोलनों ने बीज की विविधता, नवीनीकरण, संकलन और बीज स्वतंत्रता को बल दिया है। ऐसे कानून बन गए हैं, जो बीज की अखंडता, किसानों के अधिकार, आदर्शों, पारिस्थितिकी, विविधता और बीज के भावी विकास के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करते हैं। साथ ही किसानों को बीज संरक्षण और आदान-प्रदान की भी छूट देते हैं।

हमारा संघर्ष बाजार के उन तीन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ है, जो रासायनिक पदार्थ और जीएमओ बीज बेचते हैं। ये किसानों से बीज लगान के तौर पर रॉयल्टी वसूलते हैं। ये तीन प्रतिष्ठान हैं- मॉन्सेंटो-बेयर, डाउ-ड्यूपॉन्ट, सिंन्जेंटा केम चाइना।

वर्ष 1987 में मुझे एक बैठक में बुलाया गया, जहां उपस्थित व्यवसायियों का कहना था कि वे जीएमओ, पेटेंट और गैट (जीएटीटी) जैसे मुक्त व्यापार समझौतों के जरिये बीजों पर नियंत्रण रखेंगे और हर किसान को प्रत्येक मौसम में उनसे ही बीज खरीदने होंगे। हमारा संकल्प है कि मैं बीज की विविधता और उसे बचाने, संवर्द्धित करने और मुक्त आदान-प्रदान करने के किसानों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) के ट्रिप्स (ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट) के मद्देनजर बीज संरक्षण करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इस समझौते के तहत ही जीएमओ, बीजों के पेटेंट और रॉयल्टी वसूली जैसी संभावनाओं के द्वार खुले हैं। यही वजह है कि मैंने जीएमओ, बीटी कॉटन और मॉन्सेंटो द्वारा की जा रही अवैध लगान यानी रॉयल्टी वसूली को चुनौती दी है। जीएमइओ सरसों की क्या जरूरत थी? बीज स्वतंत्रता यानी बीज स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है! *(ये लेखक के निजी विचार हैं)*

कुछ कंपनियों द्वारा बीज की आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। ये सब कुछ बाजारवाद का दुष्परिणाम है जो किसानों के लिए आर्थिक बोझ के रूप में सामने आता है। नतीजा यह होता है कि किसान मजदूर बन कर रह गए हैं। बीज के मामले में आजादी खत्म तो समझो कि किसान भी स्वतंत्र नहीं रहा।

नवदान्य का अर्थ है नौ बीज, जो जैव विविधता की समृद्धि का प्रतीक हैं। ये नया उपहार भी है यानी बीज का तोहफा, जो कि जीवन का स्रोत है। लहलहाती फसल के लिए जरूरी है बीज आजादी।

सरकारी बैंक विलय से अर्थव्यवस्था को संजीवनी

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
आर्थिक मामलों के जानकार

आर्थिक विषयों पर अध्यापन, नेशनल एकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन सोशल सिक्योरिटी में शोध सलाहकार रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण में तेजी लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका मकसद सरकारी बैंकों को सुदृढ़ करना है। कहा गया है कि सरकारी बैंक गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की समस्या से जूझ रहे हैं। देश के सरकारी बैंकिंग सेक्टर में कुल मिलाकर करीब 7,38,776 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली नहीं हो पा रही है। यानी ये एनपीए में तब्दील हो गए हैं। साथ ही क्रेडिट ग्रोथ कई दशकों के निचले स्तर पर आ गई है। सरकार सरकारी बैंकों को मजबूत आकार देकर यह स्थिति पलटना चाहती है। देश और दुनिया के बैंकिंग विशेषज्ञों और रेटिंग्स एजेंसियों ने सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि भारत में सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण की दिशा में यह सकारात्मक कदम है। इससे जहां एक ओर बैंकों को परिचालन में लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर समान तरह के प्रदर्शन करने वाले बैंकों के विलय से एनपीए के समाधान की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सभी बैंक इसके दायरे में आएंगे। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के बीच तालमेल बिठाया जाएगा। बैंकों के मुनाफे का भी ख्याल रखा जाएगा। प्रस्तावित विलय बैंकिंग कंपनीज एक्ट के तहत होगा। विलय की प्रक्रिया की पहल बैंकों के बोर्डों द्वारा की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रस्ताव को सैद्धान्तिक मंजूरी देने के बाद बैंकों को कानून तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नियम के मुताबिक विलय की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण संबंधी मंत्रीमंडल के प्रस्ताव का संबंधित बैंककर्मियों द्वारा विरोध किया गया है। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की आशंकाओं को निर्मूल बताया है। पिछले दिनों ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी फिच के द्वारा प्रकाशित बैंकिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विकास दर बढ़ाने के लिए बैंकिंग संबंधी ऐसे प्रमुख सुधार की जरूरत है। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए बनी नरसिम्हन समिति ने सबसे पहले बैंक सुदृढ़ीकरण का विचार पेश किया था। सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में सुधार के लिए सात-आयामी इंद्रधनुष रणनीति बनाई है, जिसके तहत सरकार 2018-19 तक बैंकों में पुनर्पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपए देगी। रिजर्व बैंक का कहना है कि सरकारी बैंकों के विलय होने से सरकारी खजाने पर पूंजीकरण की निर्भरता कम होगी। हम आशा करें कि बैंकों के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी।

बैंक एकीकरण से वित्तीय मजबूती और डूबत कर्ज से ग्रस्त देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के सार्थक परिणाम मिलेंगे। सार्वजनिक बैंक मजबूत बनकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाएंगे।

महासमर

3126

निर्बन्ध : भयभीत

नरेंद्र कोहली के प्रसिद्ध उपन्यास से

भीम ने कहा, अब उसे हम कहां खोजें। यदि वह यहां है तो वह अकेला नहीं होगा। जहां कहीं भी होगा, स्वयं को छुपाने के लिए समूह में ही होगा। कृष्ण बोले। स्वयं को छिपाने के लिए क्यों? भीम हंसा? वह हमसे भयभीत है क्या? उसके पास तो ब्रह्मशिर देवास्त्र है। वह अकेला ही पांचालों के शिविर में घुसकर उनका वध कर सकता है। वह क्यों भयभीत होगा हमसे। भयभीत तो वे हैं ही। अकेला अश्वत्थाम ही नहीं, कृपाचार्य और कृतवर्मा भी। दुर्योधन भी तो भय के मारे ही द्वैपायन सरोवर में छिप गया था। कृष्ण बोले, यदि वह अकेला बैठ कर साधना का ढोंग करेगा तो पकड़ा जाएगा। कृष्ण चलते-चलते रुक गए, वह कौन है? शेष लोग भी रुक गए, कहां? कहां?? मध्यम तनिक शांति से। कृष्ण अपना स्वर दबाकर बोले, इस प्रकार से मुखर हो जाओगे तो वह भाग जाएगा। अब वह मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। भीम ने कहा, पर वह है कहां? बिना हाथ का संकेत किए, आंखों से देखो। कृष्ण बोले, दाईं ओर गंगा की रेत पर संन्यासियों का जो झुंड बैठा है, उसमें पीछे की ओर देखो। सबकी आंखें उस ओर चली गईं। भीम ने भी देखा उन संन्यासियों के मध्य अश्वत्थामा छिपा बैठा था। उसने सारे शरीर पर घी चुपड़कर कुश का चीर पहन रखा था। उसके अंगों पर धूल छा रही थी। हां! वेश तो बहुत परिवर्तित कर लिया था पर कृष्ण ने ठीक ही पहचाना था। भीम दौड़ा, खड़ा तो रह तू पापी! आपने कैसे उसे पहचान लिया केशव? युधिष्ठिर कुछ चकित थे। उसकी मस्तक मणि से। केवल उसके सिर पर ही वस्त्र लपेटा हुआ है। कृष्ण हंसे, कहते हैं कि इस मणि को धारण करने वाले को शत्रु का भय नहीं रहता; किंतु अश्वत्थामा को तो उसी मणि ने पकड़वा दिया है। अश्वत्थामा ने देखा कि उसे पहचान लिया गया है। भीम उसकी ओर आ रहा है। भीम की सहायता के लिए अर्जुन भी खड़ा है, कृष्ण और युधिष्ठिर भी निकट ही हैं। **क्रमशः**

बात करामात

किसे चाहिए हिसाब

व्यंग्य राही की कलम से

न खाता न बही, सरकार कहे सो सही। अजी गोली मारो आंकड़ों को। आंकड़ों को माथे पर तब ही सजाओ जब वे अपने पक्ष में हो। और पक्ष में न हो तो फिर ऐसी भावुक बातें करो कि जनता की आंखों में आंसू निकल पड़े। जब रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के आंकड़े पेश किये तो बेचारे वकील साहब ने नोटबंदी को महान बनाने के लिए जान लड़ा दी। अब चाहे सरकार कितने ही ढोल बजाती रहे परन्तु सच ये है कि नोटबंदी ऐसी असफल कवायद थी जिसने आम जनता को दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। लाइनों में खड़े-खड़े दर्जनों लोग मर गए। नोट गिनते-गिनते कितने ही बैंक कर्मचारी परलोक कूच कर गए। लाखों के धंधे बिगड़ गए। करोड़ों बेरोजगार हो गए। नए नोट छपवाने में हजारों करोड़ बेवजह खर्च हुए। और इन सबके बदले देश को क्या मिला- बाबाजी का लोटा। बड़े दावे किये थे कि काला धन सामने आ जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि जितनी करेंसी प्रचलन में थी उससे ज्यादा बैंकों में जमा हो जाए। यह कहा जा रहा था कि करीब बीस प्रतिशत काला धन अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएगा लेकिन मात्र एक प्रतिशत बाहर हुआ। यानी कुल मिलाकर देश को हजारों करोड़ की भारी चपेट लगी। बड़े लोगों ने तो तरह-तरह के उपाय करके अपना माल बचा लिया लेकिन बेचारा गरीब बारह के भाव बिक गया। मजे की बात कि नकली नोटों की बरामदगी पर भी कोई खास असर नहीं हुआ उल्टे नई करेंसी में भी नकली नोट आने लग गए। हां, नोटबंदी से एक फायदा जरूर हुआ। इस देश की जनता की आदत बेतहाशा खर्च करने की पड़ती जा रही थी वह थम गई। जब आदमी की जेब में माल ही नहीं होगा तो वह 'चाल' कैसे चलेगा। चाहे जेटली साहब कुछ भी कहते रहे लेकिन हम अपने अनुभव से कहते हैं कि नोटबंदी ने हमें तो हैरान परेशान ही किया है। पर अपना दुखड़ा किसके सामने जाकर रोए। नसीब का चक्कर मानकर चुप रह जाते हैं।

कल की बात...

नैनोट्यूब्स करेगी समुद्री पानी को मीठा

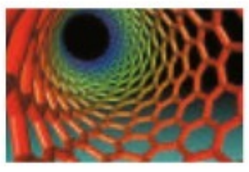

अमरीका की नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसी कार्बन नैनोट्यूब्स विकसित की हैं जो मानव के बाल से 50 हजार गुना पतली हैं। ये नैनोट्यूब्स समुद्र के पानी के खारेपन को दूर कर सकती हैं। वर्तमान में प्रचलित पानी को शुद्ध करने की विभिन्न तकनीकों के जरिए पानी की लवणीयता समाप्त नहीं हो पाती। नई तकनीक को शोध में शामिल रहीं लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेट्री की शोधकर्ता रम्या टुनुगंटला ने बताया कि नैनोट्यूब्स बेहद मुलायम है और 0.8 नैनोमीटर के व्यास वाली नैनोट्यूब सरलता से पानी शुद्ध कर उसे प्रवाहित करती है।

न्यूज रिकॉल...

देश भर में लागू हुआ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम

समूचे देश के लिए पहली बार 1 सितंबर 1947 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (आईएसटी) यानी भारतीय मानक समय लागू किया गया। भारत में कॉर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम (यूटीसी+ 05:30) को आधार माना जाता है यानी भारत ग्रीनविच मीन टाइम से 05 घंटे 30 मिनट आगे है। यही भारतीय मानक समय श्रीलंका में भी मान्य है।

मोबाइल पर पढ़ें...

पेशे की गरिमा समझें डॉक्टर
डॉ. शिल्पा जैन

जोधपुर की घटना है पेशे को झकझोर देने वाली

क्यूआर कोड को मोबाइल पर स्कैन करें और पूरा पढ़ें।

पाठक पीठ...

चिकित्सा सेवाओं की स्थिति हुई बदहाल

देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान की भी चिकित्सा सेवाएं बदहाल हैं। राजधानी जयपुर में भी स्वाइन फ्लू से निपटने के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रदेश में इस साल ही स्वाइन फ्लू से लगभग 90 मौतें हो चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग आंखे बंद करके बैठा है। प्रदेश में अब अन्य मौसमी बीमारियों का प्रकोप शुरू हो चुका है लेकिन प्रशासन सर्तक नहीं हो रहा है। मौसमी बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन को समय रहते तैयारी करनी होगी।
-शिवजी लाल, जयपुर

नोटबंदी के आंकड़ों से उपजे सवाल

रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद के जो आंकड़े जारी किए हैं वो इसकी सफलता को संदिग्ध बना रहे हैं। सरकार नोटबंदी के फायदों के बड़े-बड़े दावे करती रही है लेकिन आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। नोटबंदी से पूर्व अर्थव्यवस्था में चलन में नोटों में से 99 फीसदी नोट वापस बैंकों में आ गए। सरकार की ओर से यह माना जा रहा था कि कालाधन वापस नहीं आएगा पर आंकड़ों से सवाल उठ रहे है
-मोहित चौधरी, वाया मेल

हमसे ऐसे जुड़ें...

प्रकाशित सामग्री पर आपकी राय व विषय चयन के सुझाव हमें भेजें

@PatrikaNews
@ edit@epatrika.com